ऊर्जा तथा जलवायु परिवर्तन पर भारत-यूके का साझा बयान

1. यूके के प्रधानमंत्री श्री डेविड कैमरन तथा भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जोर दिया कि जलवायु परिवर्तन तथा सुरक्षित, सस्ती तथा धारणीय ऊर्जा की आपूर्ति भारत तथा यूके के लिए साझी रणनैतिक प्राथमिकताएं हैं। उन्होंने इन उद्देश्यों की प्राप्ति में दोनों देशों की आपसी मदद की परंपरा की सराहना की तथा इस सहयोग को और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता पर जोर दिया ।

2. दोनों प्रधानमंत्रियों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अपनी साझी अपरिहार्य प्रतिबद्धता को भी रेखांकित किया। उन्होंने जोर दिया कि देश तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावित करने वाली आज की सदी की यह एक बड़ी वैश्विक चुनौती है। उन्होंने कहा कि दोनों देश वैश्विक तापमान की वृद्धि को प्रीइंडस्ट्रियल स्तरों के ऊपर 2 डिग्री नीचे लाने के लिए दीर्घकालिक लक्ष्य साझा करते हैं। उन्होंने धारणीय विकास के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व पर बल डाला, जो ऊर्जा सुरक्षा तथा पहुंच, गरीबी उन्मूलन, आर्थिक विकास तथा नौकरियों के लिए व्यापक लाभ प्रदान करता है।

3. दोनों प्रधानमंत्रियों ने घरेलू स्तर पर कदम उठाने की अपनी प्रतिबद्धता पर बल डाला। प्रधानमंत्री श्री कैमरन ने वर्ष 2050 तक ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव को कम से कम 80% तक करने की यूके की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। यह सीमा 2008 क्लाइमेट चेंज ऐक्ट के तहत निर्धारित की गई थी, जिसमें इसके कार्बन बजट को सर्वाधिक दक्ष तरीके से प्रबंधित किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि 2005 की तुलना में भारत अपनी उत्सर्जन मात्रा को 2030 तक 33-35% कम करने के लिए प्रतिबद्ध है तथा 2030 तक गैर-जीवाश्म आधारित ऊर्जा संसाधनों से 40 संचयी विद्युत ऊर्जा संस्थापन क्षमता निर्मित की जाएगी।

4. श्री मोदी तथा श्री कैमरन ने पेरिस में UNFCCC के तहत दिसम्बर 2015 में एक महत्वाकांक्षी तथा व्यापक समझौते के लिए साथ कार्य करने की सहमति जताई, जो सभी के लिए लागू होगा।

5. दोनों प्रधानमंत्रियों ने UNFCCC के पक्षों के बीच भरोसा बहाल करने तथा एक पारदर्शक फ्रेमवर्क के लिए पेरिस अग्रीमेंट के भीतर समावेश को बढ़ावा देने के महत्व पर बल दिया, जो सभी पक्षों को उनके प्रयासों को हासिल करने की दिशा में उठाए कदमों तथा सहायता पर नियमित रूप से निगरानी रखने की जरूरत को दर्शाता है, जो दिखाएगा कि सभी पक्ष अपने संबंधित प्रयासों को पूरा कर रहे हैं।

6. प्रधानमंत्री श्री कैमरन तथा श्री मोदी ने इस तथ्य का स्वागत किया कि पेरिस अग्रीमेंट में 159 देशों ने राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान देने की इच्छा जताई है, जो वैश्विक

उत्सर्जन के शमन को 88% से ऊपर तक शामिल करता है। दोनों प्रधानमंत्रियों ने वैश्विक स्टॉक को समर्थन दिया, जिसमें कंवेंशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के क्रम में कार्य तथा सहायता दोनों शामिल हैं।

7. दोनों नेताओं ने पेरिस अग्रीमेंट को हमारे नागरिकों, व्यवसायों तथा निवेशकों को स्वच्छ ऊर्जा को अधिक वहनीय बनाने के लिए इनोवेशन तथा अनुसंधान व विकास को प्रशस्त करने की दिशा को लेकर एक स्पष्ट संकेत देने की जरूरत पर बल डाला।

8. दोनों प्रधानमंत्रियों ने जलवायु वित्त तथा विकसित देशों द्वारा संयुक्त रूप से वर्ष 2020 तक हर वर्ष US$100bn की उगाही करने की प्रतिबद्धता पर बल डाला, जो कई तरह के संसाधनों, निजी तथा सार्वजनिक दोनों से निर्मित की जाएगी। यूके तथा भारत ने विकासशील देशों में शमनकारी तथा अनुकूल कार्यों को मदद करने के लिए अनुमान्य तथा वर्धित सार्वजनिक व निजी जलवायु वित्त की अहम भूमिका की सराहना की। उन्होंने यह भी माना कि क्लाइमेट फाइनेंस से पर्यावरणीयरूप से उचित तकनीकियों तथा अनुसंधान व विकास को लागू करने में मदद मिलेगी जो इस कंवेंशन के उद्देश्यों को हासिल करने में मदद करने की दिशा में निवेश को लेकर एक बड़ा बदलाव लाएगा।

9. दोनों नेताओं ने जलवायु से जुड़े लचीलेपन पर हमारे सहयोग को रेखांकित किया, जिसमें जलवायु परिवर्तन पर भारत की राष्ट्रीय तथा राजकीय कार्य योजनाओं के लिए यूके द्वारा की जाने वाली सहायता शामिल है। यह कार्यक्रम भारत की अत्यंत संवेदनशील जनसंख्या पर जलवायु के खतरों को कम करने, अनुकूलन क्षमता को मजबूत बनाने तथा जलवायु परिवर्तन पर लोचशीलता लाने में सहायता करेगा तथा ऐसे उदाहरण पेश करेगा जिनसे अन्य देश भी सीख ले सकते हैं।

10. दोनों नेताओं ने सहमति जताई की जलवायु परिवर्तन तथा ऊर्जा पर यूके भारत सहयोग की सफलताओं को पेरिस के इंडिया पैविलियन में दिखाया जाएगा। उन्होंने जलवायु परिवर्तन से निपटने में युवाओं की भूमिका की सराहना की तथा दोनों देशों में युवा जलवायु नेटवर्क्स के बीच सहयोग स्थापित करने के एक उद्देश्य को साझा किया, ताकि समान जलवायु चुनौतियों के आविष्कारी समाधान प्रस्तुत किए जा सकें।

11. दोनों प्रधानमंत्रियों ने इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (IPCC) द्वारा उपलब्ध विज्ञान के आधार पर जलवायु परिवर्तन के एक व्यापक मूल्यांकन प्रदान करने के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने जलवायु परिवर्तन के समाधानों पर फोकस केंद्रित करने की अहमियत को रेखांकित किया तथा आइपीसीसी के भारत-यूके को-चेयर्स को मदद देने हेतु एक साथ मिलकर कार्य करने पर जोर डाला, क्योंकि आइपीसीसी की छठी मूल्याङ्कन अवधि में में जलवायु परिवर्तन के शमन हेतु मूल्यांकन विकल्पों पर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

12. दोनों प्रधानमंत्रियों ने यूके तथा भारत के बीच मौजूदा ऊर्जा सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई। भविष्य की ओर देखते हुए उन्होंने सहमति जताई कि उनके मंत्री नियमित सम्मेलनों में मुलाकात करेंगे और रणनैतिक प्राथमिकयताओं पर द्विपक्षीय सहयोग के लिए दृष्टिकोणों को साझा करेंगे तथा अवसरों की तलाश करेंगे और साथ ही ऊर्जा सहयोग हेतु अनुसंधान, विकास, प्रदर्शन तथा अततः स्वच्छ ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जाओं तथा गैस व नाभिकीय ऊर्जा को बहाल करने की दिशा में मदद करेंगे।

13. सहयोग के इस व्यापक फ्रेमवर्क के तहत, प्रधानमंत्री श्री कैमरन तथा श्री मोदी ने एक समझौता विज्ञप्ति पर हस्ताक्षर किए जाने का स्वागत किया, जो दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग को मजबूत बनाएगा, जिसमें बिजली बाजार सुधार, ऊर्जा दक्षता, ऑफशोर पवन, सौर्य ऊर्जा, स्मार्ट ग्रिड, ऊर्जा भंडारण ऑफग्रिड नवीकरणीय ऊर्जा सेवाएं शामिल हैं। उन्होंने यूके तथा भारत के बीच रणनैतिक ऊर्जा नियोजन पर सहयोग के विस्तार की भी सराहना की।

14. दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सिविल न्युक्लियर सहयोग समझौते पर वार्ता के सफल नतीजे का भी स्वागत किया, जो अधिक सहयोग के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करता है तथा यूके तथा भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच इंडियन ग्लोबल सेंटर फॉर न्युक्लियर ईनर्जी पार्टरशिप के साथ सिविल न्यूक्लियर पर संयुक्त प्रशिक्षण तथा अनुभव साझा करने के प्रयास को प्रोत्साहित करता है।

15. श्री मोदी तथा श्री कैमरन ने आविष्कारी समाधान पाने तथा स्वच्छ ऊर्जा के प्रसार तथा उनकी लागत में कमी लाने के लिए उनकी उपयोगिता तय करने में अनुसंधान तथा विकास पर वैश्विक सहयोग के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने उन प्रयासों पर साथ मिलकर काम करने पर सहमति जताई, जो इस दिशा में वैश्विक प्रयासों को बढ़ाएंगे तथा बेहतर तरीके से तालमेल स्थापित करेंगे। श्री कैमरन ने कहा कि यूके सोलर तकनीकियों तथा अनुप्रयोगों को बढ़ावा देने के लिए भारत के एक अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलाएंस के प्रयास का समर्थन करता है।

16. दोनों प्रधानमंत्रियों ने रिसर्च काउंसिल्स यूके तथा भारतीय विज्ञान तथा तकनीकी विभाग से £10 मिलियन के संयुक्त फंडिंग की घोषणा की, जो स्वच्छ ऊर्जा पर एक नवीन वर्चुअल संयुक्त सेंटर के लिए है, जो भारत-यूके स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान कार्यक्रम को £60 मिलियन तक ले जाते हैं। उन्होंने स्वच्छ ऊर्जा स्पेस में निवेश प्राप्त करने के लिए निजी सेक्टर की बढ़ती भूमिका का स्वागत किया, जो आविष्कारी कार्यों को बढ़ावा देगी तथा उन्नत तकनीकियों के इस्तेमाल की गति तेज करेगी।

17. प्रधानमंत्री श्री मोदी ने बड़े पैमाने पर निम्न लागत, दीर्घकालिक वित्त की जरूरत को रेखांकित किया, जो भारत की नवीकरणीय ऊर्जा महत्वाकांक्षाओं की आपूर्ति करती है तथा

इस दिशा में लंदन शहर द्वारा निभाई जाने वाली संभावित भूमिका का जिक्र किया। श्री कैमरन ने ग्रीन इनवेस्टमेंट बैंक के साथ यूके क्लाइमेट वेंचर की घोषणा की, जो भारत तथा अफ्रीका में नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं में कुल £200 मिलियन यूके जलवायु वित्त का निवेश करेगा।

18. प्रधानमंत्री कैमरन ने ग्रीन फाइनेंस के लिए इंडिया इनोवेशन लैब के लिए यूके फंडिंग की भी घोषणा की, जो भारत में स्वच्छ ऊर्जा वित्त की बाधाओं के आविष्कारी निदानों के लिए निजी तथा सार्वजनिक सेक्टरों को साथ लाने का भारत सरकार द्वारा समर्थित एक स्वतंत्र भारतीय प्रयास है।

19. दोनों नेताओं ने सभी के लिए सुरक्षित, सस्ती तथा धारणीय ऊर्जा की आपूर्ति हेतु कौशल तथा विशेषज्ञता साझा करने के महत्व पर जोर डाला। प्रधानमंत्री श्री कैमरन ने तकनीकी सहायता की £10 मिलियन की पंचवर्षीय योजना की घोषणा की, जो भारत के ऊर्जा क्षेत्र में राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय सुधारों को सहायता देगी।

20. प्रधानमंत्री श्री कैमरन ने स्वच्छ ऊर्जा तथा जलवायु परिवर्तन के लिए एक नई शेवनिंग फेलोशिप स्कीम की भी घोषणा की, जो तीन वर्षों में भारत के ऊर्जा सेक्टर तथा जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र के आगामी नेताओं को सामने लाएगी तथा उनके जरिए अध्ययन और सहयोग स्थापित किया जाएगा।

21. दोनों प्रधानमंत्रियों ने ऊर्जा पर भारत-यूके के व्यापारिक सहयोग को रेखांकित किया, जो दोनों ही अर्थव्यवस्थाओं में रोजगार तथा राजस्व सृजन में अहम भूमिका निभाता है। खासतौर से उन्होंने लाइटसोर्सेज प्लान का स्वागत किया जो भारत में £2 मिलियन की राशि का निवेश करेगी और 3 GW सौर बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करेगी, जिसमें सेई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड तथा यूके की तकनीकी कंपनी इंटेलिजेंट एनर्जी द्वारा भारतीय कंपनी जीटीएल के ऊर्जा प्रबंधन व्यवसाय के लिए स्वच्छ ऊर्जा प्राप्र करने के समझौते का सहयोग लिया जाएगा जो दस वर्षों के दौरान भारत के 27,400 टेलीकॉम टॉवरों को दक्ष, स्वच्छ तथा सस्ती ऊर्जा प्रदान करेगा, और इसके लिए दर्स वर्षों में £1.2 बिलियन की राशि खर्च की जाएगी। दोनों नेताओं ने दोनोंदेशों में काम करने वाली कंपनियों को सहायता देने के लिए सहमति जताई और यह माना कि बेहतर काम करने वाले ऊर्जा बाजारों तथा गैस बाजारों पर विशेषज्ञता तथा अनुभव को साझा करने से ऊर्जा सुरक्षा तथा आर्थिक विकास और लागत प्रभावी निम्न कार्बन ट्रांजिशन को बढ़ावा दिया जा सकता है।

22. प्रधानमंत्री कैमरन तथा प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों की समृद्धि को बढ़ाने के लिए ऊर्जा तथा जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में साथ काम करने के पारस्परिक लाभों के महत्व पर विशेष जोर डाला।